RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 12 APRIL TO 18 APRIL 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 29 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

रूस से खरीद पर रोक

Page 2

98% कोरोना मरीज़ों में संक्रमण की वजह ओमीक्रोन के सब वेरिएंट

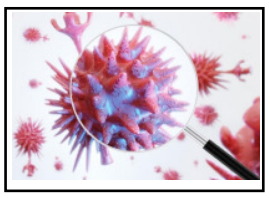

Page 3

दुनिया में बढ़ने वाली है गरीबी और भुखमरी

Page 5

editoria!

बारिश का अनुमान

गर्मी के मौसम में तापमान के औसत से अधिक रहने की चिंताओं के बीच मानसून को लेकर आशकित लेना स्वाभाविक है, पर भारतीय मौसम विभाग का आकलन है कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून की अवधि में सामान्य बारिश होगी. मानसून को लेकर यह विभाग का पहला आधिकारिक अनुमान है. यह आकलन मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुमान से अलग है, जिसमें कहा गया है कि एशिया में अल-नीनो के गंभीर होने के आसार हैं. इस आधार पर इस एजेंसी का आकलन है कि जून से सितंबर की अवधि में बरसात का औसत 86.8 सेंटीमीटर रहेगा. भारतीय मौसम विभाग ने भी अल-नीनो के मौजूद खतरे को रेखांकित किया है, पर उसका मानना है कि इससे बरसात पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हिंद महासागर के तापमान रुझान और उत्तरी गोलार्द्ध में बर्फ आवरण के नीचे रहने से अल-नीनो का प्रभाव कमतर होता जायेगा. उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग और स्काईमेट के बरसात के आकलन लगभग समान है. मौसम विभाग ने भी कहा है कि मानसून में बरसात का औसत 87 सेंटीमीटर रहेगा. यह भी कहा गया है कि सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना 67 प्रतिशत है. निश्चित रूप से यह सूचना किसानों के लिए संतोषजनक है क्योंकि हमारी अधिकांश खेती सिंचाई के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर है. बारिश का पानी नदियों और जलाशयों तथा भूजल के स्तर को भी बढ़ाता है. ऐसे में अगर सामान्य से कम बरसात से कई तरह की मुश्किलें पैदा हो सकती है. दीर्घकालिक औसत के ठीक रहने के साथ-साथ मासिक बरसात का भी सामान्य रहना जरूरी है. स्काईमेट ने आशंका जतायी है कि इसमें उतार- चढ़ाव देखने को मिल सकता है. जलवायु परिवर्तन से जो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, उनमें भारत भी है. हाल के वर्षों में अचानक भारी बारिश और बेमौसम की बरसात के अलावा हमारे देश के कई इलाकों को सूखे जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ा है. मासिक बरसात में उतार-चढ़ाव का सीधा मतलब यह है कि कुछ जगहों पर बहुत अधिक बारिश हो सकती है, तो कुछ जगहों पर कम. कृषि के लिहाज से अहम उत्तर भारत के क्षेत्रों- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बेमौसम की बरसात और ओला वृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है. उससे पहले जाड़े में तापमान अधिक होने से गेहूं की पैदावार में कमी आयी है. ऐसे में उन इलाकों को चिह्नित किया जाना चाहिए, जहां कम बारिश हो सकती है. साथ ही, हमें हर स्तर पर वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रयासरत होना चाहिए ताकि पानी की कमी न हो.

सऊदी अरब के फैसले से दुनियाभर में तेल संकट की आशंका

भारत में भी बढ़ सकते हैं दाम

नई दिल्ली। एजेंसी

सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस के देशों ने तेल उत्पादन घटाने का फैसला किया है। ऐसे में पूरी दिया के साथ भारत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था और नागरिकों की मुश्किल भी बढ़ सकती है। सऊदी अरब के तेल उत्पादन में कटौती के फैसले के बाद पूरे विश्व पर तेल संकट का खतरा मंडरा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्लेषक फतह बाइरल ने कहा है कि साल की दूसरी छमाही में इसका असर नजर आने लगेगा। सऊदी अरब, रूस और अन्य देश जो ओपेक का हिस्सा हैं उन्होंने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। बाइरल ने कहा, 'सऊदी अरब, रूस और अन्य ओपेक प्लस देशों ने तेल उत्पादन घटने का निर्णय लिया है। जब हम इसपर गंभीरता से विचार करते हैं तो पता चलता है कि साल की दूसरी छमाही में तंगी देखने को मिलेगी। भारत पर भी इसका असर साफ दिखेगा। भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। ऐसे में तेल का उत्पादन गिरने से भारत पर सीधा बोझ बढ़ जाएगा। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था और यहां के लोगों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।'

बता दें कि फिलहाल भारत बड़ी मात्रा में रूस से तेल आयात कर रहा है। इस समय रूस कम कीमत पर भारत को तेल उपलब्ध करवा रहा है। भारत वैश्विक स्तर पर बड़ा तेल का आयातक देश है। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जब कि यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था, भारत ने खरीद जारी रखी। ऐसे में रूस ने भी बैकडोर एंट्री से यूरोप को भी रिफाइंड ऑइल भेज दिया। इस साल जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रूस से तेल आयात 33 फीसदी बढ़ गया है। पिछले महीने मार्च में भारत ने हर महीने के हिसाब से 16 लाख 40 हजार बैरल का रहा। भारत इराक से भी दोगुना तेल रूस से खरीद रहा है। पहले लंबे समय से इस मामले में भारत इराक पर निर्भर हुआ करता था। इसके बाद भारत सऊदी अरब से ज्यादा आयात करने लगा। अब भी सऊदी अरब भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है।

छह बार बढ़ाने के बाद RBI ने लगाया ब्रेक, रेपो रेट 6.5 फीसदी पर बरकरार

नहीं बढ़ेगी आपके लोन की EMI

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (RBI MPC) की तीन दिन की बैठक आज खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) सुबह 10 बजे इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने राहत देते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने कहा कि सर्वसमत्ति से रेपो रेट को बरकरार रखा गया है। यानी रेपो रेट 6.50 फीसदी पर बरकरार है। लगातार छह बार बढ़ने के बाद सातवीं बार रेपो रेट ना बढ़ाकर आरबीआई ने राहत दी है।

छह बार बढ़ाने के बाद लगा ब्रेक

आपको बता दें कि आरबीआई पिछले साल मई से लेकर अब तक 250 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर चुका है। लेकिन इस बार राहत दी है। यानी आपका कर्ज और महंगा नहीं होगा और ना ही आपकी EMI बढ़ेगी। RBI ने अपनी रेपो रेट दर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसले करते हुए इसे 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हमने अर्थव्यवस्था में जारी सुधार को बरकरार रखते हुए आम सहमति से नीतिगत दर को बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने स्थिति के मुताबिक कदम उठाएंगे।

नहीं बढ़ा रेपो रेट , लोगों को मिली राहत

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले से महंगे होम लोन की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं किए जाने के बाद अब बैंक कर्ज की ब्याज दर को नहीं बढ़ाएंगे। यानी आप पर कर्ज को बोझ अभी नहीं बढ़ेगा। EMI में बढ़ोतरी से फिलहाल राहत मिली है। आपको बता दें कि रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को आरबीआई को पहले से ज्यादा ब्याज देना होता है। अगर बैंक को ज्यादा ब्याज लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे ही वसूलेंगे। बैंक कर्ज को महंगा कर देते हैं । बैंक होम लोन, कार लोन समेत सभी पर्सनल लोन को महंगा हो जाता है। आपको लोन महंगा हो जाता है, ईंध बढ़ जाती है। लेकिन इस बार आरबीआई ने लोगों को राहत दी है। रेपो रेट को पुरानी दर पर ही बरकरार रखा है।

रूस से खरीद पर रोक

भारत होकर कैसे यूरोप पहुंच रहा रूसी कच्चा तेल, रिपोर्ट में बड़ा दावा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस से सस्ते दामों पर कच्चे तेल की खरीद से भारतीय रिफाइनरियों के आउटपुट और मुनाफे को बढ़ावा मिला है। इससे वे रिफाइन्ड प्रोडक्ट्स का यूरोप में निर्यात करने लगे हैं। भारत की ओर से रूस से कच्चे तेल के आयात को लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। इसके मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूस से कच्चे तेल के रिकॉर्ड आयात से भारत को काफी फायदा मिला है। साथ ही इससे इंडिया के रिफाइनरों को यूरोप में डीजल और जेट ईंधन के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिली है, क्योंकि यूक्रेन बुद्ध को लेकर यूरोप ने रूसी प्रोडक्ट्स की खरीद बंद कर दी है। केप्लर और बोर्टेक्सा (Kpler and Vortexa) के जहाज ट्रैकिंग डेटा के आधार पर यह बात कही जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस से सस्ते दामों पर कच्चे तेल की खरीद से भारतीय रिफाइनरियों के आउटपुट और मुनाफे को बढ़ावा मिला है। इससे वे रिफाइन्ड प्रोडक्ट्स का यूरोप में निर्यात करने लगे हैं। ऐसा करने से भारत के मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले यूरोप आम तौर पर भारत से औसतन 154,000 बैरल प्रति दिन (बीपीडी) डीजल और जेट फ्यूल का आयात करता था। यूरोपीय संघ ने इसी साल 5 फरवरी को रूसी तेल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। केप्लर के आंकड़े बताते हैं कि इसके बाद भारत से यह आयात बढ़कर 200,000 बीपीडी हो गया।

यूरोप के इन देशों को निर्यात कर रहा भारत

केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय डीजल के प्रमुख यूरोपीय खरीदारों में फ्रांस, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं। भारत के जेट ईंधन निर्यात का लगभग 50ङ्क हिस्सा यूरोपीय देशों को गया। यह 2022/23 में लगभग 70,000 75,000 बीपीडी रहा जो कि पिछले वर्ष में 40,000-42,000 बीपीडी था। यूरोप को निर्यात बढ़ाने के साथ ही भारत ने अमेरिका को वैक्यूम गैस ऑयल (VGO) शिपमेंट को भी बढ़ावा दिया है। अमेरिका ने 2022/23 में भारत से लगभग 11.000-12,000 बीपीडी बीजीओ की खरीद की। यह आंकड़ा इंडिया के रिफाइनिंग फीडस्टॉक के कुल निर्यात का 65-81% है। 2021/22 में भारत ने ळए को करीब 500 बीपीडी वीजीओ का निर्यात किया था।

रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात कितना बढ़ा भारत का रूस से आयात 11 महीनों (अप्रैल-फरवरी) में करीब 5 गुना डोकर 41.56 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में रूस, भारत का 18वां सबसे बड़ा आयात भागीदार था। इस दौरान आयात 9.85 अरब डॉलर था। भारत के कुल तेल आयात का सिर्फ 0.2 प्रतिशत रूस से आया था। रूस ने जनवरी में आयात किए गए कुल तेल के 28 प्रतिशत की आपूर्ति की। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में रूस, भारत का चौथा सबसे बड़ा आयात स्रोत बन गया है। ऊर्जा आपूर्ति पर नजर रखने वाली बोर्टेक्सा के अनुसार, रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की डिस्सेदारी 1 प्रतिशत से कम थी। वह जनवरी बढ़कर 12.7 लाख बैरल प्रति दिन हो गई। इससे डिस्सेदारी 28 प्रतिशत हो गई।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक भारत चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक बन चुका है। यह अब रूस से छूट पर तेल खरीद रहा है। गौरतलब है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस से व्यापार बंद कर दिया। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल-फरवरी की अवधि के दौरान चीन से आयात लगभग 6.2 प्रतिशत बढ़कर 90.72 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र अमीरात (यूएई) से आयात 21.5 प्रतिशत बढ़कर 48.88 अरब डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान अमेरिका से भारत का आयात लगभग 19.5 प्रतिशत बढ़कर 48 अरब डॉलर पहुंच गया।

पहले लिथियम और अब REE का भंडार...

दो महीने के भीतर भारत के लिए आई 2 अच्छी खबर

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश की धरती से वैज्ञानिकों को 15 दुर्लभ तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) मिले हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 15 REE के बड़े भंडार का पता लगाया है। लैंथेनाइड श्रृंखला (Lanthanide Series) के आरईई का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सेलफोन, टीवी, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल में होता है। एनजीआरआई के वैज्ञानिकों ने अनंतपुर में सायनाइट (गैर-पारंपरिक चट्टान) की तलाश में एक सर्वे किया और इसी दौरान इन तत्वों की पहचान हुई। जिन दुर्लभ तत्वों की पहचान की गई है उनमें एलानाइट, सेरीएट, थोराइट, कोलम्बाइट, टैंटेलाइट, एपेटाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, पायरोक्लोर यूक्सेनाइट और फ्लोराइट है।

NGRI के वैज्ञानिक पीवी सुंदर राजू ने कहा कि अनंतपुर जिले के रेड्डीपल्ले और पेद्दावदागुरु गांवों से अलग-अलग आकार के जिरकोन का पता चला है।

सुंदर राजू ने बताया कि आरईई के बारे में अधिक जानने के लिए डीप ड्रिलिंग के साथ ही आगे की स्टडी की जाएगी। इन तत्वों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और डिफेंस सेक्टर में किया जाता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड टर्बाइन, जेट विमान समेत कई दूसरे उत्पादों का एक अनिवार्य घटक है।

REE का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एनजीआरआई के वैज्ञानिकों ने कहा कि आरईई और दुर्लभ-धातु का आकलन वर्तमान में आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। जिस कैंपस में यह स्टडी की जा रही है वह कडप्पा बेसिन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि अनंतपुर और चित्तूर जिलों में दनचेरला, पेद्दावदुगुरु, दंडुवरिपल्ले, रेड्डीपल्ले और चिंतलचेरवु क्षेत्र और पुलिकोंडा परिसर इन आरईई युक्त खनिजों के संभावित केंद्र है।

REE का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। 1993 में विश्व उत्पादन का 38 प्रतिशत चीन में, 33 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका में, 12 प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया में, पांच प्रतिशत मलेशिया और भारत में है। 2008 आते-आते चीन REE के 90 प्रतिशत से अधिक विश्व उत्पादन चीन में होता था और 2011 तक 97 प्रतिशत तक पहुंच गया। 1990 और उसके बाद से आरईई की आपूर्ति एक मुद्दा बन गया क्योंकि चीन की सरकार ने आरईई की मात्रा को कैप कर दिया। चीनी सरकार ने चीनी और चीन-विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनियां जो आरईई निर्यात करती थीं उसकी संख्या सीमित करना शुरू कर दिया।

भारत के लिहाज से REE को लेकर जो खबर आई वह वाकई फायदेमंद है। फरवरी के महीने में जम्मू-कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता चला। देश में पहली बार लिथियम भंडार मिला है जो जम्मू-कश्मीर में है और 59 लाख टन का अनुमान लगाया गया है। बिजली से चलने वाले वाहनों में लगने वाली बैटरी में इस धातु का इस्तेमाल किया जाता है।

सस्ती हुई CNG और PNG, गेल ने घटाए गैस की कीमत

नई दिल्ली। एजेंसी

घरों और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) की कीमतों में कटौती शुरू हो गई है। सरकार ने गैस की नई कीमतों को तय करने के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी आ जाएगी। शुक्रवार को नए मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी मिलने के बाद देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने नई कीमतें जारी कर दी है।

गेल की शहर गैस वितरण इकाई गेल गैस लिमिटेड ने गैस की मूल्य लागत में कमी के बाद रविवार को सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) की कीमतों में सात रुपये तक की कटौती की है। गेल गैस ने बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ में पीएनजी गैस की कीमत सात रुपये प्रति मानक घनमीटर (एससीएम) घटाई है। वहीं कंपनी ने अपने परिचालन वाले अन्य शहरों में पीएनजी का दाम छह रुपये प्रति इकाई घटाया है।

कंपनी ने बयान में कहा कि उसने कर्नाटक में वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सीएनजी के दाम सात रुपये प्रति किलोग्राम घटाए हैं। अन्य क्षेत्रों में सीएनजी का दाम छह रुपये प्रति किलोग्राम कम किया गया है। बयान में कहा गया है, ''गेल गैस लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण का लाभ देने के लिए नौ अप्रैल से कीमतों में उल्लेखनीय रूप से कटौती की घोषणा की है।'' देवास, मेरठ, सोनीपत, ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र, रायसेन, मिर्जापुर, धनबाद, आदित्यपुर और राउरकेला में पीएनजी की नई दर 52.50 रुपये प्रति इकाई (एससीएम) होगी। बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ के लिए यह 51.50 रुपये प्रति इकाई है। इसी तरह मेरठ और सोनीपत के लिए सीएनजी की नई कीमत 85 रुपये प्रति किलोग्राम है। देवास, ताज ट्रेपेज़ियम क्षेत्र और देहरादून के लिए यह 92 रुपये प्रति किलो; बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ के लिए 82.50 रुपये प्रति किलो; मिर्जापुर के लिए 87 रुपये प्रति किलोग्राम, रायसेन, धनबाद, आदित्यपुर, पुरी और राउरकेला के लिए 91 रुपये प्रति किलोग्राम होगी।

कंपनी ने सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के फार्मूले को संशोधन के बाद यह कदम उठाया है। संशोधित फॉर्मूले और मूल्य की सीमा की वजह से प्राकृतिक गैस की कीमत 8.57 डॉलर से घटाकर 6.5 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दी गई है। प्राकृतिक गैस को ही वाहन के लिए सीएनजी ईंधन और रसोई में खाना पकाने वाली पीएनजी में बदला जाता है।

महंगाई पर कंट्रोल से ज्यादा विकास को तरजीह क्यों?

ब्याज दर नहीं बढ़ाने के RBI के फैसले के पीछे की असली वजह

नई दिल्ली। एजेसी

ये दोधारी तलवार की तरह है। अर्थव्यस्था को संभालने में सबसे बड़ी दुविधा समझी जाती है। जब महंगाई तेजी से भागती है तो इस पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाने लगता है। इससे विकास पर बुरा असर होता है। कारोबार ठप हो सकते हैं, नौकरियों में छंटनी का दौर शुरू हो सकता है। सवाल ये उठता है कि रिजर्व बैंक के लिए महंगाई पर काबू पाना जरूरी है या विकास को बढ़ावा देना। इस बारे में रिजर्व बैंक की नीति तय करने वाली कमिटी की ताजा बैठक हुई तो उसने साफ तौर पर विकास को चुना है, लेकिन क्यों?

क्या कदम उठे : रिजर्व बैंक की मोनेटरी पॉलिसी कमिटी इस तरह के फैसले लेती है। महंगाई पर काबू पाने के लिए उसके पास एक बड़ा औजार है, रीपो रेट में बढ़ोतरी करना। रीपो रेट का मतलब बैंकों के लिए उधार देने की ब्याज दर है। रीपो रेट बढ़ेगा तो आम बैंकों को उधार महंगा मिलेगा, जिससे उनके पास मनी सप्लाई कम होगी। लोन महंगा हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि बाजार में भी नकदी की सप्लाई कम हो जाएगी। इससे महंगाई कम होने की उम्मीद रहती है, लेकिन विकास पर असर पड़ सकता है।

पिछले साल मई के बाद से रीपो रेट में लगातार बढ़ोतरी की जा रही थी। ब्याज दरों में अब कुल मिलाकर ढाई फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके बावजूद महंगाई दर फरवरी तक 6 फीसदी से ज्यादा रही है। अब जानकार सलाह दे रहे हैं कि ब्याज दरों को और बढ़ाने से पहले सरकार को थोड़ा रुककर देखना चाहिए।

क्या है लक्ष्य : रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है कि वह महंगाई दर को 2 पर्सेंट से कम और 6 पर्सेंट से ज्यादा न होने दे। लक्ष्य यह है कि महंगाई औसतन 4 पर्सेंट के आसपास रहे। इस बार अपना लक्ष्य पाए बिना रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ाने का प्रोग्राम टाल दिया। रिजर्व बैंक की मोनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो ताजा मीटिंग हुई, उससे पहले तक हालात अलग थे। कमिटी के अंदर ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर असंतोष था। मगर, कमिटी ने सहमति से ब्याज दरों में बढ़ोतरी टालने का फैसला किया। आगे भी इस बढ़ोतरी को

टाला जा सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इतना भर कहा है कि हम महंगाई के मामले पर आगे सतर्क रहेंगे।

महंगाई में नरमी : ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच इस वित्त वर्ष में महंगाई दर 5.2 पर्सेंट रह जाने का अनुमान है। ये समझा जा रहा है कि कि आने वाले समय में महंगाई कम हो सकती है। रबी की फसल अच्छी होने का अनुमान है। मॉनसून भी दमदार रहने का अंदाजा लगाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी जरूरी कमॉडिटीज की कीमतों में कमी देखी जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में फिलहाल बहुत तेजी के आसार नहीं बताए गए हैं। समझा जा रहा है कि इसी वजह से रिजर्व बैंक की कमिटी ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी टालने का फैसला किया।

आगे क्या होगा: बहरहाल, महंगाई इसी तरह रही और ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गईं तो गरीबों को महंगाई चुभेगी। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला कहते हैं कि रिजर्व बैंक की कमिटी का फैसला बाजार में ज्यादातर लोगों के विचार से अलग रहा। हमें अनुमान है कि रिजर्व बैंक ने विकास और महंगाई को लेकर जो अनुमान लगाया है, साल के अंत में दोनों उससे कम ही होंगे। इससे ब्याज दरों में और नरमी आ सकती है।

ग्रोथ के साथ : रिजर्व बैंक की मोनेटरी पॉलिसी कमिटी के कदम को ग्रोथ के पक्ष में देखा जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5 फीसदी ग्रोथ रेट का अनुमान है। इस वक्त कम ही देश दुनिया में हैं, जहां इतनी अच्छी विकास दर है। कई ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने भारत के विकास को लेकर अपने अनुमानित आंकड़ों में कमी की है। ये माना जा रहा है कि दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती छा रही है। बैंकिंग सेक्टर में संकट की वजह से वित्तीय स्थिरता के मुद्दे पर शंकाएं जताई जा रही हैं।

हाल के समय में धीमी होती खपत ने आर्थिक जानकारों की चिंता बढ़ाई है। साथ ही निजी निवेश में भी कमी आई है। अमेरिका और यूरोप के सेंट्रल बैंकों ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के सिलसिले को रोका नहीं है। समझा जा रहा है कि बैंकिंग संकट के बाद वहां भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर थामना पड़ सकता है।

IMF ने भारत के इकनॉमिक ग्रोथ का अनुमान घटाकर 5.9 प्रतिशत किया

नई दिल्ली। एजेंसी

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मंगलवार को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (FY24) के लिए भारत के इकनॉमिक ग्रोथ अनुमान को 20 बेसिस पॉइंट्स घटाते हुए 6.1 फीसदी से 5.9 प्रतिशत कर दिया। IMF का यह अनुमान अन्य मल्टीलेट्रल डिवेलपमेंट बैंकों की तुलना में सबसे कम है। वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3 प्रतिशत और एशियन डेवेलपमेंट बैंक ने 6.4 प्रतिशत की गति से बढ़ने के अनुमान जताया है। IMF ने अनुमान लगाया है कि ग्लोबल ग्रोथ अगले वर्ष मामूली रूप से बढ़कर 3 प्रतिशत तक पहुंचने से पहले 2023 में 2.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ जाएगी। वहीं, क्रय शक्ति समानता के मामले में प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन में भारत की वृद्धि वित्त वर्ष 2023 में 5.8 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

महंगाई व घाटे पर कम की चिंता:

IMF ने अपनी ताजा द्विवार्षिक विश्व आ थिक आउटलुक में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन के वित्त वर्ष 2023-24 में 4.9 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान लगाया, जो बीते वित्त वर्ष में 6.7 प्रतिशत थी। साथ ही IMF ने भारत के करेंट अकॉउंट डेफिसिट (CAD) के अनुमान को जीडीपी के 2.6 प्रतिशत से घटाकर 2.2 प्रतिशत कर दिया है।

UPI पेमेंट पर मिलेगी EMI की सुविधा

पैसे नहीं होने पर भी कर सकेंगे खरीदारी, जानिए कितनी होगी लिमिट

नई दिल्ली। अब आप यूपीआई पेमेंट पर भी ईएमआई की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से इस सुविधा की शुरुआत की गई है। बैंक के मुताबिक, ळझ्ध भुगतान के लिए ंश्ध सुविधा का फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान, फैशन परिधान, ट्रैवल और होटल बुकिंग जैसी कई कैटेगरी में लिया जा सकता है। बैंक के मुताबिक, उसने क्यूआर कोड को स्कैन करके किए गए यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की है। बैंक ने बताया कि कस्टमर बैंक के पे लेटर ऑप्शन बाई नाओ, पे लेटर का इस्तेमाल करके ईएमआई सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। जो ग्राहक बैंक की पे लेटर सुविधा के योग्य होंगे वह इसके माध्यम से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट के बाद कस्टमर अपनी सुविधा के हिसाब से किस्तों में बैंक को यह अमाउंट वापस कर सकेंगे।

कितनी है लिमिट

बैंक के मुताबिक, पहली बार यह सुविधा शुरू की गई है। अब कस्टमर सिर्फ एक स्टोर पर जरूरी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके और भुगतान करके प्रोडक्ट को तुरंत खरीद सकते हैं। इस सुविधा के जरिए कस्टमर 10 हजार रुपये तक का यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसे कस्टमर को तीन, छह या नौ महीनों में आसान सी किस्तों में बैंक को वापस करना होगा। बैंक के मुताबिक, इस नई सुविधा को जल्द ही ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी शुरू किया जाएगा।

ऑनलाइन कर सकते हैं खरीदारी

आईसीआईसीआई बैंक ने साल 2018 में पे लेटर की सुविधा शुरू की थी। यह सुविधा ग्राहकों को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस तरीके से छोटे आइटम तुरंत खरीदने में सक्षम बनाती है। कस्टमर इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। ग्राहक इससे बिलों का भुगतान कर सकते हैं और दुकानों पर किसी भी मर्चेंट यूपीआई आईडी को तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। इस सुविधा से ग्राहकों को काफी फायदा मिला है।

98% कोरोना मरीज़ों में संक्रमण की वजह ओमीक्रोन के सब वेरिएंट

जीनोम टेस्ट से पता चलीं और भी बातें

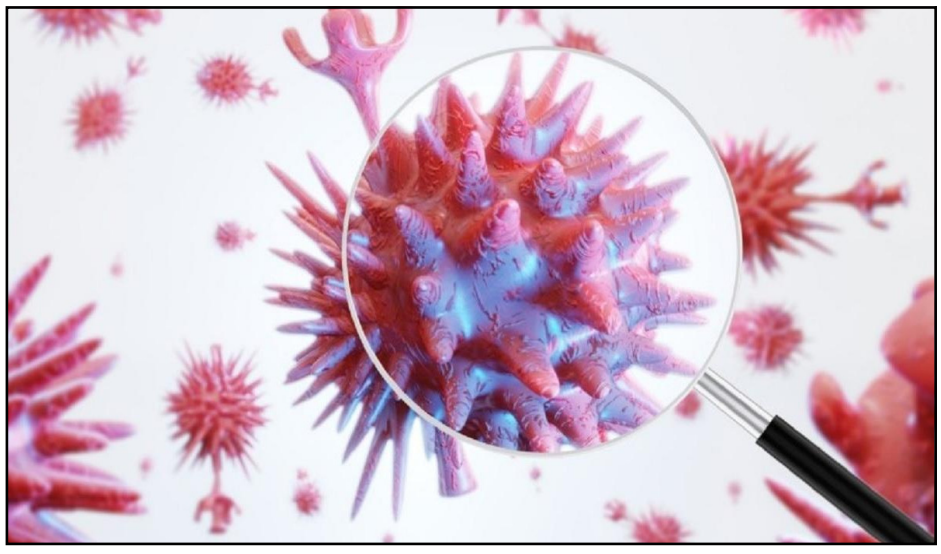

नई दिल्ली। एजेंसी

एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बार संक्रमण में आए उछाल की वजह ओमीक्रोन का नया सब वेरिएंट XBB.1.16 मिल रहा है। इन दिनों दिल्ली में कोरोना संक्रमित होने वालों में से 71 प्रतिशत में XBB.1.16 वेरिएंट पाया गया है। इस समय दिल्लीवालों को XBB और इसके सब वेरिएंट ही सबसे ज्यादा बीमार कर रहे हैं। इस वेरिएंट की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बहुत तेजी से फैलता है और इम्युनिटी को क्रॉस कर संक्रमित करने की क्षमता रखता है। राहत की बात यह है कि अब तक यह वेरिएंट सीवियर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन जैसे-जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की अस्पतालों में एडमिशन की संख्या भी बढ़ रही है और कोविड की वजह से जान भी जा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की सलाह है कि लोगों को अब ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है और कोविड बिहेवियर का पालन करने की आदत डाल लेनी चाहिए।

273 सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग

एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि अभी 273 सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग की गई है। इसमें से 269 मामले यानी 98.6 प्रतिशत में XBB और इसका सब वेरिएंट ही मिला है। इसमें से सबसे ज्यादा XBB.1.16वेरिएंट मिला है। 273 में से 196 सैंपल में XBB.1.16 वेरिएंट मिला है, जो 71.79 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बाकी में भी XBB का ही सब वेरिएंट मिला है। 45 सैंपल में XBB.2.3 मिला है जो 16.48 प्रतिशत है। इसके अलावा XBB.1.5 वेरिएंट 16 सैंपल में मिला है, जो कुल संक्रमितों का 5.86 प्रतिशत है। जबकि BA.5.3 वेरिएंट 2 सैंपल में पाया गया है। उन्होंने कहा कि हमें कोविड को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। रविवार को एक मरीज की मौत की प्राइमरी वजह कोविड मिली है, इसलिए अब सबको कोविड बिहेवियर का पालन करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, भीड़ में जाने से बचना चाहिए और लक्षण दिखने पर जांच करानी चाहिए।

दिल्ली में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो तब सबसे पहले अल्फा वेरिएंट था। इसके बाद बीटा और फिर गामा वेरिएंट फैला। सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ डेल्टा वेरिएंट, जिसने दिल्ली में तबाही मचा दी थी। इस बीच वायरस में कई और बदलाव हुए, लेकिन इसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव हुआ। यह वेरिएंट बाकी से काफी तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। ओमिक्रॉन में अब तक 600 से ज्यादा लाइनेज सर्कुलेशन हो चुका है, इस वजह से इसके स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त म्यूटेशन हुआ है, जो अब XBB.1.16 वेरिएंट बन गया है।

अस्पतालों में भी बढ़ रहे हैं मरीज

आकाश हॉस्पिटल के रेस्पिरेट्री विभाग के डॉक्टर अक्षय बुद्धराजा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक ज्यादातर लोगों में बीमारी हल्की ही है। दो से तीन दिन फीवर रह रहा है, सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की दिक्कत हो रही है। लेकिन, पिछले दो दिनों से ऐसे मरीज भी आ रहे हैं, जिन्हें भर्ती करना पड़ रहा है। उनमें सीवियर कोविड मिल रहा है। खासकर जिन्हें डायबिटीज है या लंबे समय से किडनी की बीमारी है और वो डायलिसिस पर हैं, उनके लिए यह खतरनाक हो रहा है। एक मरीज वेंटिलेटर पर भी है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में अचानक कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ गई है।

XBB.1.16 वेरिएंट कितना खतरनाक है

डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा कि इसमें संक्रमण फैलने की गति बहुत ज्यादा है। हालांकि, देश में 95 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास इम्युनिटी है, चाहे वह नेचुरल इंफेक्शन की वजह से हो या फिर वैक्सीनेशन की वजह से। हमारे पास बचाव है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह तेजी से फैल रहा है, यह खतरनाक संकेत है, इसलिए अब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। लक्षण दिखे तो जांच करानी चाहिए, संक्रमण पाए जाने पर आइसोलेट हो जाएं ताकि वो दूसरे को संक्रमण न दे सके।

प्रिकॉशन डोज पर क्या करें आम लोग

इंफेक्शन एक्सपर्ट डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन साफ है। अभी केवल 60 साल से ऊपर और बीमार लोगों को ही प्रिकॉशन डोज की सलाह दी गई है। इसलिए हर किसी को यही गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। अगर किसी ने प्रिकॉशन डोज ले रखी है और डोज लिए छह महीने से ज्यादा बीत गए हैं तब भी उन्हें नई गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए।

ईपीएफओ ने हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए बढ़ाई डेडलाइन

3 मई तक करना होगा ये काम

नई दिल्ली। एजेंसी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारकों के लिए हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने इसके लिए अब 3 मई की समयसीमा निर्धारित की है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को उन कर्मचारियों को एक और बदलाव की परमिशन दी थी, जो 1 सितंबर 2024 तक मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस मेंबर रहेंगे। ये मेंबर पेंशन के लिए अपने वास्तविक सैलरी का 8.33 फीसदी तक योगदान कर सकते हैं. अगर पेंशन योग्य वेतन का 8.33 फीसदी 15,000 रुपये प्रति माह है।

डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई

कहा जा रहा था कि ईपीएफओ ने इस मामले में फैसला लेने में काफी देरी कर दी है, जिससे अंशधारकों को कम समय मिलेगा। ऐसे में यही संभावना जताई जा रही थी कि इस प्रक्रिया की समयसीमा आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, ऐसा हुआ भी कि ईपीएफओ ने डेडलाइन आगे बढ़ाकर 3 मई कर दी।

ये कर्मचारी चुन सकेंगे इस विकल्प को

ईपीएफओ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी किया है. इसके मुताबिक 'ऐसे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवा में थे और 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत संयुक्त विकल्प का उपयोग नहीं कर सके हैं, वे अब 3 मई 2023 या उससे पहले ऐसा कर सकते हैं.।'

इस समय कर्मचारी और कंपनी दोनों ही एम्प्लाई के वास्तविक वेतन, महंगाई और रिटेनिंग भत्ते (अगर कोई हो तो) का 12 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है। जबकि, कंपनी की ओर से कर्मचारी को दिया जाने वाला 12 प्रतिशत योगदान ईपीएफ में 3.67 प्रतिशत और ईपीएस में 8.33 प्रतिशत के तौर पर बांटा जाता है। केंद्र सरकार एक कर्मचारी की पेंशन में 1.16 प्रतिशत का योगदान करती है, जबकि कर्मचारियों का इस पेंशन योजना में कोई योगदान नहीं होता।

घर बैठे ही आधार कार्ड के लिए दे सकेंगे फिंगरप्रिंट

आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं

भोपाल। एजेंसी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने ऐसा टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने को समझौता किया है, जिसका इस्तेमाल किसी भी वक्त, कहीं से भी किया जा सकेगा। टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित होने के बाद फिंगरप्रिंट का प्रमाणीकरण घर बैठे हो सकेगा। नई प्रणाली एक ही बार में अंगुलियों के निशान लेगी व प्रमाणीकरण सफलता दर हासिल करने में सहायता करेगी। आइटी मंत्रालय के मुताबिक यूआइडीएआइ और आइआइटी बॉम्बे अंगुलियों के निशान के लिए मोबाइल कैप्चर सिस्टम के साथ एकीकृत लाइवनेस मॉडल बनाने के लिए शोध करेंगे। नए सिस्टम से आधार प्रमाणीकरण और मजबूत, सरल व सुरक्षित हो जाएगा।

ऑथेंटिकेटर की दिशा में बड़ा कदम

यह यूनिवर्सल ऑथेंटिकेटर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। आइआइटी अपने राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (एनसीईटीआइएस) की मदद से यूआइडीएआइ के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। प्रोजेक्ट का नेतृत्व यूआइडीएआइ के हाथ में होगा, जो लगातार आधार प्रणाली के विकास के लिए अनुसंधान और विकास पर काम कर रहा है।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि नई प्रणाली एक ही बार में कई उंगलियों के निशान ले लेगी और प्रमाणीकरण सफलता दर हासिल करने में सहायता करेगी। एक बार नई प्रणाली लागू हो जाने के बाद आधार (Aadhaar) इकोसिस्टम में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि होगी.

सभी जगहों पर बढ़ गया है आधार का यूज

बता दें कि आधार ने आखिरी पायदान पर खड़े इंसान को बैंकिंग सुविधाओं (ट्रांजेक्शन) से जोड़ने का काम किया है। आधार कार्ड का इस्तेमाल लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। वर्तमान में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा देश में चलाई जा रही लगभग 900 जनकल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है।

122 करोड़ में बिका कार का नंबर प्लेट

नई दिल्ली। एजेंसी

खबर की हेडलाइन पढ़कर आपका दिमाग घूम गया होगा, लेकिन खबर और हेडलाइन दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। वास्तव में एक कार का नंबर प्लेट 122 करोड़ रुपये में बिका है। ये दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर नंबर प्लेट के लिए इतनी बड़ी रकम क्यो? सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। इसे खरीदने वाले का नाम भी पता नहीं चल सका, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है, उसे जानकर आप उसकी तारीफ करेंगे। दुबई में इस खास नंबर प्लेट के लिए नीलामी हुई, जिसमें सबसे ऊंची बोली 55 मिलियन दिरहम की लगाई गई। यानी करीब 122.6 करोड़ रुपये में कार का एक नंबर प्लेट बिका है।

दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट

ऋ्ह कार नंबर प्लेट P7 दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट बन गया है। मोस्ट नोबल नंबर्स चैरिटी नीलामी में इस नंबर प्लेट की नीलामी हुई। सबसे ऊंची बोली पाकर ये दुनिया के सबसे महंगे नंबर प्लेट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। नंबर प्लेट के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले शख्स ने शर्त रखी कि उसका नाम गुप्त रखा जाए। जुमेराह के फोर सीजन्स होटल में नीलामी कार्यक्रम रखा गया। बड़े-बड़े कारोबारियों और शेख ने इसमे हिस्सा लिया। 15 दिरहम से बोली की शुरुआत हुई तो 55 दिरहम तक पहुंच गई।

P7 नंबर प्लेट की नोबेल नंबर प्लेट के तौर पर जाना जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले पैनल 7 में बैठे व्यक्ति ने की थी, जिसके बाद से इसका नाम पी7 रख दिया गया। ये किसी भी नीलामी में बिका सबसे महंगा नंबर प्लेट साबित है। इसी के बाद इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। इस बार नीलामी में किस व्यक्ति ने 55 दिरहम की सबसे ऊंची बोली लगाई इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाई है। बोली लगाने वाले शख्स ने ये शर्त रखी थी कि उसका नाम सामने नहीं लाया जाए। उसके पीछे खास वजह है।

वजह जानकर करेंगे तारीफ

नीलामी में जमा रकम को खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस नीलामी से जमा की गई रकम का इस्तेमाल रमजान के दौरान लोगों को खाना खिलाने के लिए किया जाएगा। इस रकम को वन बिलियन मील्स अभियान को सौंप दिया जाएगा। गौरतलब है कि ये संस्था गरीबों और जरुरतमंद लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करवाती है। इसकी नींव दुबई के उपराष्ट्रपति एवं शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने रखी थी। इस नीलामी में करीब 97,920,000 दिरहम एकत्र किए गए, जिसका इस्तेमाल अब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग उस गुमनाक शख्स की खूब तारीफ कर रहे हैं। लोगों कमेंट कर रहे हैं कि उसने जानबूझकर ऊंची बोली लगाई, ताकि ज्यादा रकम नेक काम के लिए जमा हो सके।

दुनिया में बढ़ने वाली है गरीबी और भुखमरी, IMF ने घटाया ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान

कमजोर देशों की होगी बुरी हालत

नई दिल्ली । एजेंसी

इस साल दुनिया में गरीबी और भुखमरी बढ़ने का खतरा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी घ्इ ने यह बात कही। आईएमएफ ने साल 2023 के लिए वैश्विक ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया है। आईएमएफ चीफ ने कहा कि वर्ल्ड इकॉनमी (World economy) के 2023 में 3 फीसदी से भी कम की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह पिछले साल के 3.4 फीसदी से काफी कम है। इससे वैश्विक गरीबी और भुखमरी का खतरा बढ़ गया है। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि ग्लोबल ग्रोथ रेट के अगले पांच वर्षों में तीन फीसदी के करीब ही रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा, 'यह 1990 के बाद से हमारा मध्यम अवधि का सबसे कम ग्रोथ पूर्वानुमान है।'

गरीब देशों की बढ़ेगी कठिनाई

आईएमएफ की एमडी ने कहा कि ग्लोबल ग्रोथ रेट में गिरावट एक गंभीर झटका होगा, जिससे कम आय वाले देशों के लिए कठिनाई बढ़ जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट पिछले साल 3.4 प्रतिशत रही थी।

बढ़ सकती है गरीबी और भुखमरी

जॉर्जीवा ने यह चेतावनी भी दी कि वैश्विक वृद्धि के सुस्त पड़ने से गरीबी और भुखमरी बढ़ सकती है, जो कोविड संकट के कारण पहले ही चुनौती बनी हुई है। उन्होंने इसे एक खतरनाक ट्रेंड बताया। उनकी यह टिप्पणी आईएमएफ और विश्व बैंक की वाशिंगटन में अगले सप्ताह होने वाली सालाना 'वसंत बैठकों' से पहले आई है।

इन दो बड़ी समस्याओं पर हो सकती है चर्चा

यह सालाना बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। साथ ही इस समय कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज संकट भी छाया हुआ है। पाकिस्तान भी इनमें से एक है। कर्ज के बोझ के चलते ये देश ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं।

पहली क्लास में 6 साल से पहले नहीं मिलेगा दाखिला! जानें आ रहा क्या नया नियम

नई दिल्ली । एजेंसी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत 3 से 8 साल के उम्र के बच्चों के एजुकेशन स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है और दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी इसे अपनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने सभी हितकारकों से 20 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं। नए सिस्टम के तहत क्लास 1 से पहले तीन क्लासें होंगी, जबकि अभी नर्सरी और केजी होती है। फाउंडेशनल स्टेज के नए ढांचे के साथ अब क्लास 1 से पहले एक और क्लास जुड़ रही है। अभी 3 और इससे ऊपर की उम्र में बच्चा नर्सरी में दाखिला लेता है और केजी में उसकी उम्र 4ट्ट होती हैं और क्लास 1 में 5ट्टसाल का बच्चा दाखिला लेता है मगर नए सिस्टम के साथ बच्चा 3 की उम्र से पढ़ाई शुरू करेगा, क्लास 1 से पहले तीन साल की पढ़ाई करेगा और फिर क्लास 1 में 6ट्ट की उम्र में दाखिला लेगा।

शिक्षा निदेशालय की ओर से कहा गया है कि वो इस नए स्ट्रक्चर को अपनाने का इरादा रखता है। नए स्ट्रक्चर के साथ नया करिकुलम और अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी। पढ़ाने के नए तरीके, पढ़ने-सिखाने के नई साम्रगी की जरूरत भी होगी, जिसके लिए टीचर्स, अभिभावक, स्टूडेंट्स, प्रबंधक समितियों, शिक्षा संस्थाओं, स्कूल असोसिएशन, पेशेवर लोगों, सब्जेक्ट विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। 'स्कूलों में चल रहा किताबों, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का बिजनेस', बढ़ी फीस से परेशान पैरेंट्स की एक और शिकायत

हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने 'नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज 2022' को लागू किया है, जो कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा का नया डिजाइन है। इसे नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने एनईपी के तहत तैयार किया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी के लिए 3 साल का स्ट्रक्चर तय किया है। प्री स्कूल में बच्चों के लिए कोई किताबें नहीं होंगी, उन्हें कहानियों, खिलौनों, एक्टिविटी के जरिए सिखाया जाएगा।एनईपी में यह उम्र सीमा बहुत अहम मानी गई है, क्योंकि यह सीखने का महत्वपूर्ण पड़ाव है।

बीमारी के बहाने से मारी छुट्टी तो AI खोल देगा पोल, जानिए कैसे करेगा काम?

नई दिल्ली। एजेंसी

अक्सर लोग बीमारी का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी कर लेते हैं। सर्दी, खांसी, जुखाम का बहाना करके लोग बॉस से छुट्टी मांग लेते हैं, लेकिन अब ये बहाना काम नहीं करेगा। बीमारी के बहाने छुट्टी लेने वालों की अब पोल खुलने वाली है। इस तरह का बहाना बनाकर छुट्टी लेने वालों की पोल एआई (Artificial intelligence) खोल देगा। जब से चैट जीपीटी (ChatGPT), ओपन एआई (OpenAI), गूगल बार्ड (Google Bard) जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए हैं रोज नई चीजें सामने आ रही है। जो एआई आपके काम को आसान बनाता है, अब वो कुछ लोगों के लिए गले की फांस बन जाएगा। अब तक लोग एआई का इस्तेमाल अपने काम को आसान बनाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब यहीं एआई उनकी पोल खोलने वाला है।

बहाने से छुट्टी लेने वालों की खुलेगी पोल

एक रिसर्च में में ये बात सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि AI आवाज की मदद से पता लगाने में सक्षम हो पाएगा कि सामने वाले को सर्दी जुखाम या खांसी है या नहीं। इस तकनीक की मदद से लोगों की सर्दी-जुकाम को पता लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि ये तकनीक उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जो सर्दी, जुखाम का बहाना देकर बार-बार ऑफिस से छुट्टी लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए AI का ये टूल मुश्किल बढ़ाने वाला है।

कैसे करेगा काम

एक रिसर्च के मुताबिक AI आपकी आवाज की टोन को पहचान कर बता देगा कि आपको सच में सर्दी, जुकाम है या नहीं। रिसर्च में कुछ लोगों के वॉइस पैटर्न पर स्टडी की गई। ये लोग ऐसे थे, जो कह रहे थे कि उन्हें सर्दी जुखाम है। लेकिन इस रिसर्च में केवल 111 लोगों में ऐसे निकले, जिन्हें सच में सर्दी जुकाम था। टेस्ट के दौरान लोगों के वोकल पैटर्न को टेस्ट किया। हार्मोनिक्स का इस्तेमाल कर पता लगाया गया कि सच में सर्दी जुखाम है या नहीं। जिन्हें सच में सर्दी या जुखाम होता है, उनका वोकल पैटर्न इर्रेगुलर रहता है। इस तकनीका का इस्तेमाल कर बीमार है या नहीं इसका पता लगाया जाता है।

इस वजह से महिलाएं नहीं पहनती पैरों में सोने का आभूषण, भगवान विष्णु से जुड़ी है परंपरा

सोना-चांदी, हीरे-मोती पहनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है. खास कर सुहागिन महिलाएं सोने और चांदी के बने आभूषण को अधिक पहनती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं पैरों में चांदी की ही पायल क्यों पहनती हैं. सोने की पायल आखिर क्यों नहीं पहनती? आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर महिलाएं अपने पैर में सोने की पायल क्यों नहीं पहनती तो चलिए जानते हैं. दरअसल धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु को सोना अति प्रिय होता है और सोने को नाभि के नीचे नहीं पहना जाता. अगर आप अपने पैरों में सोना पहनते हैं तो धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं. इतना ही नहीं भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी को भी सोना अत्यंत प्रिय होता है. यह भी मान्यता है की पैरों में सोना पहनने से भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. जिससे घर परिवार में आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है. हालांकि दूसरी तरफ बताते हैं कि सनातन धर्म में स्वर्ण में शक्ति का वास होता है. स्वर्ण सौभाग्य का प्रतीक होता है. स्वर्ण को पैरों में धारण करने से माता पार्वती और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं. लेकिन देश में ऐसे कई जगह पर सोने के पायल लोग पैरों में धारण करते हैं. ऐसा अनुचित है. हमारे शास्त्रों के अनुसार स्वर्ण की पूजा होती है. स्वर्ण की प्रतिमा बनाई जाती है, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी का मंगल ग्रह खराब है तो उसे सोने की अंगूठी पहननी चाहिए.

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

समृद्धि और खुशियों का त्यौहार है बैसाखी

इतिहास की इन दो घटनाओं ने बना दिया और भी खास

श्री रघुनंदन जी
9009369396
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद
अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट

बैसाखी मुख्य रूप से समृद्धि और खुशियों का त्योहार है। इसके मनाए जाने का मुख्य आधार पहली वैसाख को पंजाबी नववर्ष का प्रारंभ फसलों के पकने और कटने की किसानों की खुशियां हैं। इतिहास की दो घटनाओं ने बैसाखी के पर्व को अधिक यादगार और महत्वपूर्ण बना दिया। ये दो घटनाएं हैं- 1699 की बैसाखी को सिख धर्म के दशम गुरू गुरू गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ का निर्माण किया तथा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियावाले बाग में देश की आजादी के लिए हजारों लोग शहीद हुए। 1699 की बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब (पंजाब) में बैसाखी के विशाल समागम में गुरू गोविंदसिंग ने बड़े नाटकीय ढंग से देश और कौम के लिए शहीदी के जज्बे की पांच सिक्खों की परीक्षा ली। गुरू और सिख धर्म के प्रति पांचों सिक्खों की निष्ठा और समर्पण को देखते हुए गुरू साहिब से उन्हें अमृत छकाया और पांचों प्यारों का नाम दिया।

लोहे के बाटे (बड़ा कटौरा) में सतलुज नदी का पानी लेकर उसमें शकर मिलाकर गुरूजी ने अपनी कटार से हिला दिया और ये जल अमृत कहलाया। पांचों प्यारों को अमृत छकाने के बाद गुरू साहिब ने स्वयं भी पांचों प्यारों से अमृत ग्रहण किया।

अमृत छकना एक तरह से धर्म और देश की खातिर कुर्बानी के लिए तैयार रहने का संकल्प था। इसी समागम में गुरूजी ने सिक्खों को पांच ककार-कच्छ (कच्छा), कंगा, केस, कृपाण और कड़ा अनिवार्य रूप से धारण करने का निर्देश दिया। खालसा पंथ का यह स्वरूप आज भी यथावत विद्यमान है।

पद्म पुराण में कहा गया है कि वैसाख माह में प्रातः स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान है। वैसाख शुक्ल सप्तमी को महर्षि जह्नु ने अपने दक्षिण कर्ण से गंगाजी को बाहर निकाला था। इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। अतः सप्तमी को गंगाजी के पूजन का विधान है।

भगवान बद्रीनाथ की यात्रा की शुरुआत भी इसी माह होती है। बैसाखीबंगाल में 'पैला (पीला) बैसाख' नाम से, दक्षिण में 'बिशु' नाम से और केरल, तमिलनाडु, असम में 'बिहू' के नाम से मनाया जाता है।

सिख समाज बैसाखी के त्योहार को सामूहिक जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसीलिए यह त्योहार पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार और खरीफ की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक बताया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हिन्दू पंचांग के अनुसार गुरु गोविन्द सिंह ने वैसाख माह की षष्ठी तिथि के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी दिन मकर संक्रांति भी थी। इसी कारण से बैसाखीका पर्व सूर्य की तिथि के अनुसार मनाया जाने लगा। प्रत्येक 36 साल बाद भारतीय चन्द्र गणना के अनुसार बैसाखी 14 अप्रैल को पड़ती है।

बैसाखी का त्योहार बलिदान का त्योहार है। मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने तेगबहादुर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था, तभी गुरु गोविंदसिंह ने अपने अनुयायियों को संगठित कर 'खालसा पंथ' की स्थापना की थी।

अलग-अलग राज्य, अलग-अलग पर्व : बंगाल का नया वर्ष वैशाख महीने के पहले दिन 14 अप्रैल से शुरू होता है। बंगाल में इस दिन से ही फसल की कटाई शुरू होती है। इस दिन नया काम करना शुभ मानकर नए धान के व्यंजन बनाए जाते हैं।

मलयाली न्यू ईयर विशु वैशाख की 13-14 अप्रैल से ही शुरू होता है। केरल में इस दिन धान की बोवनी आरंभ होती है। हल और बैलों को रंगोली से सजाकर पूजा कर बच्चों को उपहार दिए जाते हैं। तमिल लोग 13 अप्रैल से नया साल पुथांदू मनाते हैं। असम में लोग 13 अप्रैल को नया वर्ष बिहू मनाते हैं।

कब है वैशाख अमावस्या? बन रहे 3 संयोग, लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें स्नान मुहूर्त

वैशाख अमावस्या वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाएगी. किसी भी माह की अमावस्या तिथि धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है. इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. वैशाख अमावस्या के दिन स्नान और दान से पितर भी प्रसन्न होते हैं. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस बार वैशाख अमावस्या के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं. वैशाख अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है और दक्षिण भारत में इस तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है. इसके अलावा वैशाख अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग बना है. आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या कब है और स्नान दान का मुहूर्त क्या है?

वैशाख अमावस्या 2023 तिथि मुहूर्त

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, 19 अप्रैल को सुबह 11:23 बजे से वैशाख माह की अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी और यह ति?थि 20 अप्रैल को सुबह 09:41 बजे तक मान्य रहेगी. उदयाति?थि के आधार पर वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल को है.

सर्वार्थ सिद्धि योग में वैशाख अमावस्या का स्नान-दान

वैशाख अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 05:51 बजे से लेकर रात 11:11 बजे तक है, वहीं प्रीति योग दोपहर 01:01 बजे से रात तक मान्य है. जिन लोगों को वैशाख अमावस्या का स्नान और दान करना है, वे सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग में स्नान और दान कर सकते हैं.

वैशाख अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण

इस साल का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या के दिन 20 अप्रैल को लगेगा. सूर्य ग्रहण का समय सुबह 07:04 बजे से लेकर दोपहर 12:29 बजे तक है. हालांकि इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल नहीं होगा. ऐसे में वैशाख अमावस्या का स्नान दान प्रातःकाल में ग्रहण पूर्व कर सकते हैं.

वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती

दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है, जबकि उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को शनि देव का जन्मदिवस मनाया जाता है. वैशाख अमावस्या के दिन आप शनि देव की पूजा कर लें और उनके उपाय कर लेंगे तो उनकी महादशा में लाभ होगा.

वैशाख अमावस्या का महत्व

वैशाख अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान आदि कर सकते हैं. फिर आप भगवान विष्णु की पूजा करें या भगवान श्रीकृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा करें. इससे आपके कष्ट दूर होंगे और पाप मिटेंगे. जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आएगी.

दुनियाभर में मेड इन इंडिया की धूम

10 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट

एपल का निर्यात चार गुना बढ़ा

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एपल (Apple) को भारत में अपने कारोबार से जबरदस्त फायदा हुआ है। अमेरिकी कंपनी एपल ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत से पांच अरब डॉलर यानी करीब 40,000 करोड़ रुपये के आईफोन (iPhone) एक्सपोर्ट किए। यह वित्त वर्ष 2022 की तुलना में चार गुना अधिक है। जानकारों का कहना है कि एपल आईफोन भारत से पांच अरब डॉलर एक्सपोर्ट का आंकड़ा छूने वाला पहला ब्रांड है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एपल ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में आईफोन का प्रॉडक्शन तेजी से बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत से कुल 10 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए गए। भारत ने किसी फाइनेंशियल ईयर में पहली बार यह सफलता हासिल की है।

एपल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत से 1.6 अरब डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे। हालांकि आईफोन के कुल प्रॉडक्शन में भारत की हिस्सेदारी अब भी महज पांच परसेंट हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के डेटा के मुताबिक दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग (Samsung) ने पिछले वित्त वर्ष में भारत से 3.5 से चार अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया। भारत अब ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, मिडल ईस्ट, जापान, जर्मनी और रूस जैसे विकसित देशों को भी स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट कर रहा है। इस बारे में एपल और सैमसंग ने उसे भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। एपल 18 अप्रैल को मुंबई और 20 अप्रैल को दिल्ली में अपना रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। इसके लिए कंपनी के सीईओ टिम कुक (Tim Cook) के भारत आने की संभावना है।

स्टोर्स से किसे होगा नुकसान

इस बीच रिटेलर्स को आशंका है कि मुंबई और दिल्ली में एपल का स्टोर खुलने से उनके ग्राहकों की संख्या में 50 से 60 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। आईफोन की कुल सालाना बिक्री में इन दो शहरों की हिस्सेदारी 20 फीसदी है। कुछ का कहना है कि एपल पहले अपने स्टोर्स के लिए स्टॉक रिलीज करेगी। इससे बाकी रिटेलर्स को नुकसान हो सकता है। हालांकि कंपनी के सूत्रों ने इस आशंका को खारिज किया है। उनका कहना है कि एपल के रिटेल स्टोर खोलने से पूरे रिटेल ईकोसिस्टम को फायदा होगा।

इससे पहले एपल एक्सक्लूसिव एपल प्रीमियम पार्टनर स्टोर्स, बड़े रिटेलर्स और ट्रेड एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रॉडक्ट्स बेचती थी। कंपनी का कहना है कि नए रिटेल लोकेशंस से उसके बिजनस का भारत में विस्तार होगा। 20 अप्रैल से भारत में कंपनी के ग्राहक नए प्रॉडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकेंगे। मुंबई के एक रिटेलर ने कहा कि अपने स्टोर्स ने कंपनी ग्राहकों के लिए एक्सपीरिएंस सेंटर भी बनाएगी। इससे रिटेलर्स को कुछ नुकसान होगा। अमेरिका और यूरोप में नए प्रॉडक्ट के लॉन्च के दौरान एपल के स्टोर्स के बाहर भारी भीड़ देखी

जाती है।

80 परसेंट ग्राहक छोटे शहरों से

ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नवनीत पाठक ने कहा कि कंपनी नए लॉन्च के दौरान दिल्ली और मुंबई में इसी तरह का हाइप क्रिएट करना चाहेगी। एपल के मौजूदा ग्राहक नया प्रॉडक्ट खरीदने से पहले इन स्टोर्स में जाना चाहेंगे। रिटेल स्टोर्स में सभी नए प्रॉडक्ट्स एक्सपीरिएंस के लिए शोकेस नहीं किए जाते हैं। इसलिए नए लॉन्च के दौरान इन स्टोर्स में कस्टमर्स की संख्या 50 से 60 फीसदी कम हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कंपनी रिटेलर्स को पर्याप्त स्टॉक देगी? पाठक ने कहा कि एपल ने अब तक इस बारे में कोई बात नहीं की है। हालांकि कुछ लोग इसे ज्यादा तरजीह नहीं देते। उनका कहना है कि एपल के 80 फीसदी नए ग्राहक छोटे शहरों से आते हैं। ऐसे में एपल के दो स्टोर्स ने ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।

11 प्रतिशत चढ़ गया वाइन मेकर कंपनी का शेयर

आने वाले दिनों में बन सकता है रॉकेट!

नई दिल्ली। एजेंसी

वाइन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी और एकमात्र लिस्टेड कंपनी सुला विनयार्ड्स के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। बाजार खुलते ही यह 11 फीसदी तेजी के साथ 389.75 रुपये पर पहुंच गया। मार्च तिमाही में दमदार प्रदर्शन के दम पर कंपनी के शेयरों में उछाल आई। मार्च तिमाही में कंपनी की ग्रोथ में सालाना आधार पर 15 फीसदी तेजी आई है। यह कंपनी दिसंबर में अपना आईपीओ लाई थी। इस कंपनी की देश के एलीट एंड प्रीमियम1 वाइन बिजनस में 60 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है। कंपनी की ब्रांड सेल वॉल्यूम 10 लाख केस पार कर गई। एक केस में 750 मिली की 12 बोतल होती है। Elite & Premium वाइन की बिक्री पहली बार पांच लाख केस पार कर गई है। कंपनी के अपने ब्रांड और वाइन टूरिज्म बिजनस ने मार्च तिमाही में रेकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया। वाइन टूरिज्म इस दौरान 18 फीसदी बढ़ गया जबकि सालाना

आधार पर इसमें 30 फीसदी की तेजी आई। सुला विनयार्ड्स का कहना है कि प्रॉविजनल बेसिस पर कंपना का नेट रेवेन्यू चौथी तिमाही में अपने ब्रांड्स से 104.3 करोड़ और वाइन टूरिज्म से 12.4 करोड़ रुपये रहा। वाइन टूरिज्म में रूम रेवेन्यू, फूड और बेवरेजेज की सेल, मर्केंडाइज और दूसरी एंशिलियरी सर्विसेज आती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का वाइन टूरिज्म बिजनस 80 करोड़ रुपये को टच कर गया जो 2019 में 44 करोड़ रुपये था। कंपनी का कहना है कि अगले साल यह 100 करोड़ रुपये पहुंच सकता है।

क्यों आ सकती है तेजी

देश में वाइन की खपत तेजी से बढ़ रही है और इसका फायदा सुला विनयार्ड्स को भी मिल रहा है। पिछले महीने ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी की कवरेज शुरू की थी और 475 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ इसे खरीदने की सलाह दी थी। सीएलएसए के एनालिस्ट्स का कहना है कि दुनियाभर में लोगों का झुकाव बीयर और वाइन जैसे लो अल्कोहल बेवरेज सेगमेंट की तरफ हो रहा है। इससे सुला को फायदा होगा। सुला ने दिसंबर में 357 रुपये के भाव पर आईपीओ के जरिए 960 करोड़ रुपये जुटाए थे और यह 22 दिसंबर को लिस्ट हुई थी।

गर्मी की दस्तक से पहले ही पीक पर पहुंची आइसक्रीम की बिक्री

नई दिल्ली। एजेंसी

हर साल गर्मी में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है। गर्मियां खत्म होते ही बिक्री कम हो जाती है। लेकिन इस बार गर्मी की दस्तक से पहले ही आइसक्रीम की बिक्री ने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइसक्रीम की ताबड़तोड़ बिक्री हो रही है। आम तौर पर वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में वार्षिक बिक्री का 60% या कुछ ब्रॉन्डों के लिए इससे भी ज्यादा हो सकता है। ग्रेविस फूड्स (बास्किन रॉबिन्स) के सीईओ मोहित खट्टर के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में सर्दियों के महीनों में भी मजबूत बिक्री दिख रही है। सर्दियों के महीनों में भी कंपनी की औसत बिक्री लगभग गर्मियों के महीनों में बिक्री के समान स्तर पर थी। जानकारों के मुताबिक, अब ऑफ सीजन में आइसक्रीम खाने का चलन बढ़ रहा है।

इस वजह से बढ़ी बिक्री

आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। इसकी एक वजह अब आइसक्रीम की आसानी से उपलब्धता है। अब कई कंपनियां आइसक्रीम की घरों में 10 मिनट में डिलीवरी कर रही हैं। लोगों के पास अब अच्छे फ्रीज भी हैं। इसमें आइसक्रीम को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस सोढ़ी के मुताबिक, आइसक्रीम की खपत में मौसमी बदलाव निश्चित रूप से कम हो रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि घरों में आइसक्रीम की खपत बढ़ गई है। इसके अलावा, एक दशक पहले की तुलना में आज आइसक्रीम के कई फ्लेवर उपलब्ध हैं।

आइसक्रीम की सबसे बड़ी कंपनी अमूल ने हाल ही में कहा था कि वह देश में 100 आइसक्रीम पार्लर शुरू करने की योजना बना रही है, जो प्रीमियम आइसक्रीम फ्लेवर पेश करेगी। उद्योग स्तर पर, आइसक्रीम का बिजनस करीब 17३ की दर से बढ़ रहा है। आजकल लोग अपनी छोटी-छोटी खुशियों को आइसक्रीम के साथ मनाना पसंद करते हैं। आज, लोगों के लिए आइसक्रीम का सेवन करने के कई अवसर हैं। कंपनियों के मुताबिक, इस साल महिला दिवस पर आइसक्रीम की बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिला था।

रीन्यूएबल एनर्जी वर्कफोर्स को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी और फेनिस एनर्जी की साझेदारी

नई दिल्ली। एजेंसी

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और रीन्यूएबल एनर्जी समाधानों के अग्रणी प्रदाता, फेनिस एनर्जी ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपस्किलिंग और माइक्रो-ऑन्तरप्रेन्योरशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की शुरुआत की है। यह साझेदारी हमारे देश में एनर्जी के स्वच्छ स्रोतों के ट्रान्जिशन में सहायता और गति देगी। रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आवश्यक विभिन्न कौशल सेटों में 1 लाख से अधिक लर्नर्स को ट्रेनिंग दी जानी सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रोग्राम विशेष रूप से भारत के लिए दो प्रमुख विकास उद्देश्यों के उद्देश्य से है - देश भर में जॉब्स/माइक्रो-ऑन्तरप्रेन्योर्स को विकसित करने के लिए मजबूत अवसर पैदा करना और जलवायु संकट से निपटना। इस साझेदारी के माध्यम से दोनों संस्थाएं अपस्किलिंग के लिए उम्मीदवारों की पहचान करेंगी और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और प्रैक्टिकल कोर्सवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित करेंगी और सभी ग्रेजुएट लर्नर्स का प्लेसमेंट सुनिश्चित करेंगी। प्रोग्राम को सेल्स एंड मार्केटिंग मॉड्यूल, इन्स्टॉलेशन और कमीशनिंग, ऑपरेशन्स और मेन्टीनेन्स और सॉफ्टवेयर डिजाइन में लर्नर्स को प्रशिक्षित करने के लिए निर्देशित किया गया है।रीन्यूएबल एनर्जी में प्रगति के साथ, साझेदारी को सोलर के साथ शुरू करने और पायलट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और एक समयावधि के लिए स्टोरेज और हाइड्रोजन के साथ-साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार किया गया है। उम्मीदवारों को मोबिलाइज़ करने, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग देने और 'ग्रीन वर्कफोर्स' में समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न ट्रेनिंग पार्टनर्स और स्किल एजेंसियों के साथ काम चल रहा है। एनएसडीसी के सीईओ वेद मणि तिवारी ने कहा, 'रीन्यूएबल एनर्जी दुनिया का भविष्य है, और 1 लाख उद्यमियों और जॉब्स को बनाने के विज़न के साथ, हम फेनिस के साथ सहयोग करने के लिए

उत्साहित हैं। यह साझेदारी बढ़ते ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्डस्ट्री की मांगों को पूरा करने के लिए भारत के वर्कफोर्स के कौशल को बढ़ाने और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरा विज़न हमारे देश के युवाओं को ग्रीन एनर्जी के लिए दुनिया के ट्रान्जिशन का नेतृत्व करना है।

शक्ति पम्पस् की 'स्विचिंग सर्किट टू स्टार्ट सिंगल फेज - इंडक्शन मोटर' को मिला पेटेंट

भारत और विदेशों में शक्ति पम्पस् को मिला यह तीसरा पेटेंट

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एनर्जी एफिशिएंट पम्पस् और मोटर्स के अग्रणी निर्माता शक्ति पम्पस् इंडिया लिमिटेड, को 'स्विचिंग सर्किट टू स्टार्ट सिंगल फेज-इंडक्शन मोटर' के लिए पेटेंट मिला है। कंपनी को यह पेटेंट 'इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

ऑर्गनाइजेशन' द्वारा दिया गया है। पेटेंट एक्ट, 1970 के प्रावधानों के अनुरूप इस पेटेंट की वैधता पेटेंट फाइल करने की तारीख से 20 वर्ष की होगी। भारत और विदेशों में कंपनी ने अब तक 3 पेटेंट प्राप्त किए हैं और 27 पेटेंट फाइल कर चुके हैं। श्री दिनेश पाटीदार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने इस महत्वपूर्ण पेटेंट मिलने पर कहा: 'हमें बेहद खुशी है कि शक्ति पम्पस् की रिसर्च टीम द्वारा किए गए इन प्रयासों को मान्यता मिल रही है। नेतृत्व करने की हमारी इच्छा और क्षमताओं ने हमें उन प्रोडक्ट्स का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया है जो न केवल अद्वितीय हैं बल्कि हमारे ग्राहकों और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। अब तक हमने एक ठोस प्लेटफार्म तैयार कर लिया है और अपनी मजबूत ब्रांड मान्यता के साथ, हम आगे भी उद्योग में सकारात्मक योगदान जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं जो हमें अपने इन्वेस्टर्स के लिए उत्साहजनक परिणाम देने में मदद करेगा।'

श्री पाटीदार ने बताया कि आम तौर पर, सिंगल-फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए, कैपेसिटर का उपयोग करने वाले एक कंट्रोल बॉक्स की आवश्यकता होती है। साथ ही सबमर्सिबल मोटर्स में राइजर केबल में एक एडिशनल कंडक्टर की जरूरत होती है। ये कैपेसिटर सर्किट और वोल्टेज के उतार - चढ़ाव में जटिलताओं की संभावनाओं को बढ़ाते हैंध इस अविष्कार की मदद से इन जटिलताओं से बचा जा सकता है, एवं राइजर केबल में कंडक्टर्स की अतिरिक्त लागत बचाई जा सकती है। यह आविष्कार राइजर केबल्स में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की समस्या को भी दूर करता है और पैनल और कैपेसिटर की तुलना में स्विचिंग में सटीकता बढ़ाता है।

लखपति बना देगा ChatGPT

इस काम के 16 लाख रुपये बांट रही कंपनी

नई दिल्ली। एजेंसी

ChatGPT के कारण कई लोगों में अपनी नौकरी जाने का डर है लेकिन ChatGPT आपको लखपति बना सकते हैं। जी हां, बस इसके लिए आपको इसमें खामियां ढूंढनी पड़ेगी। दरअसल, चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई ने मंगलवार को कहा कि वह अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में खामियों की रिपोर्ट करने वाले यूजर्स को 20,000 डॉलर (लगभग 16.41 लाख रुपये) तक की पेशकश करेगी।

बग की गंभीरता के हिसाब से मिलेगा पैसा

ओपनएआई बग बाउंटी प्रोग्राम, जो मंगलवार को लाइव हुआ, लोगों को उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए बग की गंभीरता के आधार पर पुरस्कार प्रदान करेगा, जिसमें प्रति बग 200 डॉलर (लगभग 16,412 रुपये) का पुरस्कार दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी कंपनियां अक्सर प्रोग्रामर्स और एथिकल हैकर्स को अपने सॉफ्टवेयर

सिस्टम में बग की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम का उपयोग करती हैं। बग बाउंटी प्लेटफॉर्म Bugcrowd पर डिटेल के अनुसार, ओपनएआई ने शोधकर्ताओं को चैटजीपीटी की कुछ फंक्शनैलिटी और ओपनएआई सिस्टम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ डेटा शेयर करने के फ्रेमवर्क का रिव्यू करने के लिए इन्वाइट किया है। प्रोग्राम में ओपनएआई सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस्ड गलत या मैलेशियस कंटेंट शामिल नहीं है। यह कदम इटली में चैटजीपीटी को प्राइवेसी रूल्स के संदिग्ध उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है, जो अन्य यूरोपीय देशों में नियामकों को जनरेटिव एआई सर्विसेस का अधिक बारीकी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। Microsoft कॉर्प समर्थित ध्र्जहैंध का ChatGPT, जिसने नवंबर में लॉन्च होने के बाद से दुनिया भर में तूफान ला दिया है, ने कुछ यूजर्स को सवालों के त्वरित जवाबों से प्रभावित किया है और अशुद्धियों के साथ दूसरों के लिए परेशानी का कारण बना है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।